IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

समान नागरिक संहिता का विधिशास्त्र बहुसंस्कृतिवाद और धर्मनिरपेक्षता के लिए ख़तरा

डॉ सैय्यद कलीम अख्तर

(असिस्टेंट प्रोफेसर)

स्कूल का लॉ

श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय

अमरोहा, उत्तर प्रदेश

भूमिका

हम सभी स्वामी विवेकानन्द को देश के युवाओं के प्रेरक गुरु के रूप में याद करते हैं। उन्होंने भारतीयों को अपने देश की महान आध्यात्मिक विरासत की उचित समझ दी और इस प्रकार उन्हें अपने अतीत पर गर्व किया। शिकागो[1] में दिये गये उनके जबरदस्त भाषण को कौन भूल सकता है? उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा: -

"मुझे उस राष्ट्र से होने पर गर्व है जिसने पृथ्वी के सभी धर्मों और सभी देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में इस्राएलियों के सबसे शुद्ध अवशेष को इकट्ठा किया है, जो उसी वर्ष दक्षिणी भारत में आए और हमारे साथ शरण ली, जब उनके पवित्र मंदिर को रोमन अत्याचार ने टुकड़ों में तोड़ दिया था। मुझे उस धर्म से होने पर गर्व है, जिसने भव्य पारसी राष्ट्र के अवशेषों को आश्रय दिया है और अभी भी उनका पालन-पोषण कर रहा है। भाइयों, मैं आपको एक भजन की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करूँगा जो मुझे याद है कि मैं बचपन से ही इसे दोहराता रहा हूँ, जिसे हर दिन लाखों मनुष्य दोहराते हैं:-

"जिस प्रकार अलग-अलग धाराओं के स्रोत अलग-अलग स्थानों पर होते हैं और वे सभी अपना पानी समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार, हे भगवान, मनुष्य अलग-अलग प्रवृत्तियों के माध्यम से जो अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं, भले ही वे टेढ़े या सीधे दिखाई देते हों, वे सभी आपकी ओर जाते हैं"

वर्तमान सम्मेलन, जो अब तक आयोजित सबसे प्रतिष्ठित सभाओं में से एक है, गीता में उपदेशित अद्भुत सिद्धांत की पुष्टि, विश्व के लिए एक घोषणा पत्र है:-

जो कोई भी मेरे पास आता है, किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुँचता हूँ; सभी मनुष्य उन रास्तों से संघर्ष कर रहे हैं जो अंततः मुझ तक पहुंचते हैं। वर्तमान समय में, भारत सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक है।भारत देश विश्व गुरु बनने में अपना कदम बहुत मजबूती से रख रहा है, भारत के इस प्रगति से उन सभी लोगों के मुंह बंद कर रहा है जो भारतीयों को गरीब, भिखारी और असहाय आदि कहते हैं।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा:- "मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊँगा, मैं ईसाई चर्च में प्रवेश करूंगा और क्रूस के सामने घुटने टेकूंगा, मैं बौद्ध मंदिर में प्रवेश करूंगा जहां मैं बुद्ध और उनके विधान की शरण लूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा और उस हिंदू के साथ ध्यान में बैठूंगा" जो उस प्रकाश को देखने की कोशिश कर रहा है जो हर किसी के दिल को रोशन करता है।उनके भाषण में शामिल बिन्दु पर जोर देना चाहिए वे हम शब्द पर चल रहे है कि न तो उन्होंने और न ही स्वामी अरबिंदो ने "वे और हम" की भाषा बोली।[2]

विवेकानन्द ने भारत की एक अद्भुत तस्वीर विश्व पटल पर पेश की जो भारत की पहचान के रूप में हर देशवासी के दिल में बस गयी। उनके द्वारा चलायी गयी मुहिम को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाया गया और अंततः भारतीय संविधान में अनेक विचारधारा ,सम्प्रदाय और पंथ के भावना को शामिल किया गया। भारत एक ऐसा देश है जहां देश के हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं चाहे वह धर्म को लेकर हो या भाषा को लेकर या फिर अन्य मामले ।

भारत देश की पहचान कभी भी विशिष्ट या एकरूप नहीं रही। भारत देश या उनकी विचारधारा विविधता, बहुलवाद, समावेशिता और अनेकता में निहित है। अब समय आ गया है कि लोग इन आदर्शों में अपने विश्वास की पटल पर पुष्टि करें और प्रतिक्रियावादी तत्वों को महान भारतीय सभ्यता को एक सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करे। समान नागरिक संहिता एक महान लेकिन आवश्यक अवधारणा नहीं है। वर्तमान प्रास्थिति समान नागरिक संहिता की ऐसी अवधारणा को पेश करने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि आचार संहिता, अनुष्ठान, विश्वास और यहां तक कि पोशाक और भोजन भी धर्म द्वारा शासित होते हैं और देश के नागरिक अपने रोजमर्रा जिंदगी से अलग नहीं करना चाहता, समाज में केवल अराजकता लाएगा. यदि समान नागरिक संहिता को लागू करने की आवश्यकता पड़ती है तो इसकी अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब संसद में सभी दलों के प्रतिनिधि से इस बहस किया जाए तभी देश इस बिन्दु पर निर्णय लेने की शक्ति हो।

समान नागरिक संहिता की संकल्पना और इसकी गलत धारणा

इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि विविध कानूनों को समायोजित करना और प्रत्येक समुदाय के लिए उपयुक्त एक समान या नियमित कोड का विवरण देना सुविधाजनक या व्यावहारिक है। संविधान का अनुच्छेद 44, जो सभी भारतीयों के लिए एक समान सामान्य सिविल संहिता की चर्चा करता है, सम्पूर्ण भारत देश में वर्तमान समय में बहस का विषय बना हुआ हैं। इस तरह के कोड के लिए बोलने वाले व्यक्तियों का मूल तर्क यह था कि यह संभवतः भारत में शामिल हो सकता है क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों ने 1937 तक आसानी से "सामान्य पारंपरिक हिंदू नागरिक संहिता" अपना ली थी, जब "मुस्लिम लीग-ब्रिटिश गठबंधन" ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) एप्लीकेशन एक्ट के माध्यम से मुसलमानों पर शरिया लागू करके उन्हें विभाजित कर दिया था।

जब हम लॉर्ड कार्नवालिस के समय से लेकर 1937 के अधिनियम तक के मामले की गहराई से जांच करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 1937 से पहले केवल मुसलमानों का एक छोटा सा अल्पसंख्यक हिंदू रीति-रिवाज अपनाता था। वास्तव में, यहां तक कि इस वर्ग को कच्छी मेमन्स अधिनियम, 1920 और महोमेदान विरासत अधिनियम (1897 का द्वितीय) जैसे कानूनों के तहत "महोमद ए लॉ" पर निर्णय लेने का अधिकार था। मुसलमानों के बहुसंख्यक हिस्से के संबंध में, यह दिखाने के लिए पर्याप्त पुष्टि और सबूत हैं कि उन्होंने मुस्लिम कानून को अपनाया, न कि हिंदू सामान्य संहिता को। इस प्रकार, यह तर्क कि हम व्यक्तिगत कानून के अनुसार एक साथ जुड़े हुए थे, का संबंध है, और गलत है। कॉर्नवालिस से पहले, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में घोषणा की थी कि:-

"...कि विरासत, विवाह और ऐसे अन्य धार्मिक मामलों में,मुसलमानों के संबंध में कुरान के कानून और जेंटू [हिंदुओं] के संबंध में शास्त्र के कानूनों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा.."[3]

हालाँकि जब 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी, तब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ अछूते रह गए थे। उपरोक्त प्रकरणों से पता चलता है कि पर्सनल लॉ को एक साथ लाने पर कभी विचार नहीं किया गया और इसका कारण यह नहीं था कि अंग्रेज बड़े पैमाने पर विस्फोट से डरते थे। वे ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से कुशल थे। समान नागरिक संहिता जैसी सामान्य आपराधिक संहिता को लागू करने से बचने का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने कभी भी इस

तरह का कार्य करने की आवश्यकता नहीं समझी। उन्हें कभी भी उन परिस्थितियों को संभालने में अपनी जीवन शक्ति और शक्ति को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो उनके लिए उत्पादक नहीं थीं। मैकाले ने अपने लेख में भारत की ऐसी परिस्थिति पर जोर देते हुए कहा है कि प्रशासन को लोगों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि वे अपने व्यवसाय को स्वयं से बेहतर जानते हैं।

जब हिंदू विवाह कानून बनाया गया, तो सभी संप्रदायों और समूहों में हिंदुओं के बीच बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या इससे सचमुच हिंदुओं में द्विविवाह की प्रथा कम हो गई है? आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं. इसने वास्तव में जो किया वह यह है कि ऐसे विवाहों में दूसरे पति-पत्नी को उनके भरण-पोषण, रहने की व्यवस्था आदि के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, और उन्हें उनके गौरव से वंचित कर दिया जाता है, जैसा कि अदालती प्रक्रियाओं में उन्हें वेश्या, मालकिन और रखैल के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो अधिकारों के बिना हैं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शांति के अस्तित्व के उनके अधिकार और जीवित रहने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जैसे संविधान महिलाओं के कुछ वर्ग को सुरक्षित करता है और जो व्यक्ति सिस्टम में फिट नहीं होते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जा सकता है। इसके अलावा, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम और हिंदुओं में युवा लड़कियों के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र की सिफारिश से बाल विवाह में कमी आई है। एक बार फिर, आंकड़े अलग कहानी दर्शाते हैं क्योंकि हिंदुओं में कम उम्र में विवाह करने वालों की संख्या मुसलमानों में बाल विवाह से अधिक है। बाल विवाह तब कम होता है जब समुदाय की वित्तीय स्थिति बढ़ती है, न कि कोई कानून होने के कारण। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि समान नागरिक संहिता की अवधारणा सांप्रदायिक है और कानून सुधारों के स्थान की जमीनी हकीकत की उपेक्षा करती है।

यदि समान नागरिक संहिता को सांप्रदायिक रूप से विकृत और अल्पसंख्यकों के प्रति शत्रुतापूर्ण तरीके से बनाया जाएगा, तो इसमें बहुत सारे विरोधाभास होंगे और गड़बड़ी पैदा होगी। मीडिया ने न्यायपालिका द्वारा कानून की प्रगति में हासिल किए गए आवश्यक मील के पत्थर की उपेक्षा की है। मेरा मानना है कि पर्सनल लॉ के दायरे में ही कानूनों में सुधार के लिए यह एक रचनात्मक तरीका है।

हमें समान नागरिक संहिता की नहीं, बल्कि "धार्मिक विश्वास" के सार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न धर्मों के समुदायों के बीच अधिकारों की निरंतरता की आवश्यकता है। इसके लिए हमें परिचय के बाद "भीतर से सुधार" को अपनाना होगा, इसी तरह हिंदू कानून में सुधार किया गया, ईसाई कानून में सुधार किया गया और बिना किसी बड़ी राजनीतिक बहस के मुस्लिम कानून में सुधार किया गया है। वर्तमान चर्चा अनुचित

प्राचीन महाकाव्यों का विधिशास्त्र

समान नागरिक संहिता के समर्थकों और विरोधियों के बीच मुख्य संघर्ष "यथास्थिति या परिवर्तन" को लेकर है। हमारी माननीय न्यायपालिका अपने लिए यथास्थिति की अवधारणा का पालन करती है क्योंकि यह मिसाल के नियम का पालन करती है। फिर भी, न्यायपालिका की यथास्थिति समय की मांग के साथ बदलती है और जब न्यायपालिका खुद को सक्षम पाती है और जब उसे अपने कानूनों के लिए अधिक मजबूत विकल्प मिलता है। हर जगह ऐसा ही होगा. यह अवधारणा उत्तम है क्योंकि इसमें लचीलापन शामिल है। जब हम यूसीसी के लिए बहस करते हैं, तो हमें वही नियम लागू करना चाहिए। हमें व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित कानूनों को लागू करना चाहिए यदि हम पाते हैं कि जो लोग प्रभावित होने वाले हैं वे सक्षम हैं या वे "समझते हैं" कि उनके पास अन्य बेहतर विकल्प हैं। भारत में यह अवधारणा दोनों ही तरीकों से विफल है। एक वे लोग जो इस कानून को लागू करने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें आम जनता की स्थिति और क्षमताओं से कोई लेना-देना नहीं है, जो धर्म के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं, और दूसरे वे लोग हैं, आम लोगों ने अपनी आँखें बंद कर ली हैं, चाहे वह अपने अधिकारों के बारे में हो या कर्तव्यों के बारे में।

ऐसी अवधारणा की झलक हमें मनुस्मृति में मिलती है, जो कहती है:-

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् । आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥

अनुवाद 1: वेद, पवित्र परंपरा, पुण्य पुरुषों के रीति-रिवाज और स्वयं की खुशी, वे पवित्र कानून को परिभाषित करने के चार गुना साधन होने की घोषणा करते हैं।

अनुवाद 2: वेद, परंपरा, अच्छे लोगों का आचरण और जो स्वयं को अच्छा लगता है, वह धर्म का चतुर्गुण है। - मनुस्मृति 2.12

लेविंसन का कहना है कि हिंदू कानून में श्रुति और स्मृति की भूमिका मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में है, और इसकी परंपरा इस सिद्धांत को विकसित करती है कि "किसी विशेष मामले के तथ्य और परिस्थितियां निर्धारित करती हैं कि क्या अच्छा या बुरा है"। लेविंसन कहते हैं, बाद के हिंदू ग्रंथों में धर्म के चार स्रोत शामिल हैं, जिनमें आत्मनस्तुति (किसी के विवेक की संतुष्टि), सदाचार (गुणी व्यक्तियों के स्थानीय मानदंड), स्मृति और श्रुति शामिल हैं। [4]

जैसा कि स्थानीय मध्यस्थों द्वारा समझाया गया था, ब्रिटिशों ने हस्तक्षेप से बचकर और कानून प्रथाओं को अपनाकर सत्ता का प्रयोग किया। इस प्रकार औपनिवेशिक राज्य ने उन्नीसवीं सदी के अंत तक अनिवार्य रूप से पूर्व-औपनिवेशिक धार्मिक और राजनीतिक कानून और संघर्षों को कायम रखा। [5] उदाहरण के लिए, भारत में व्यक्तिगत कानूनों के संबंध में औपनिवेशिक नीति 1772 में गवर्नर-जनरल हेस्टिंग्स द्वारा इस प्रकार व्यक्त की गई थी:

"विरासत, विवाह और ऐसे अन्य धार्मिक मामलों में मुसलमानों के संबंध में कुरान के कानूनों और जेंटू [हिंदुओं] के संबंध में शास्त्र के कानूनों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा"[6] ।

-वॉरेन हेस्टिंग्स, 15 अगस्त, 1772

मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून शरिया-आधारित बने रहे, जबकि एंग्लो-हिंदू कानून विवाह, तलाक, विरासत जैसे मामलों पर किसी भी पाठ से स्वतंत्र बनाया गया था और एंग्लो-हिंदू कानून भारत में सभी हिंदुओं, जैन, सिख और बौद्धों को कवर करता था [7]। 1872 में, ब्रिटिश राज ने भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम लागू किया, जिसमें रोमन कैथोलिकों को छोड़कर सभी संप्रदायों के भारतीय ईसाइयों के लिए विवाह, तलाक और गुजारा भत्ता कानून शामिल थे।[8]। कानूनी बहुलवाद का विकास, जो कि व्यक्ति के धर्म के आधार पर अलग कानून है, भारत में शुरू से ही विवादास्पद था।

शरीयत अधिनियम 1937 का आलोचनात्मक विश्लेषण

शरीयत अधिनियम 1937 मुसलमानों द्वारा पर्सनल लॉ में रुचि का परिणाम था। इसने पूर्व अधिनियमन में ऐसी हर व्यवस्था को रद्द कर दिया, जो उन स्थितियों में 'मुसलमान कानून' को निरस्त करने की अनुमति देती थी, जहां पार्टियां मुस्लिम थीं। किसी भी स्थिति में, अंग्रेजों ने इस अधिनियम को सभी मुसलमानों पर नहीं थोपा। इसे भौतिक अधिदेश बना दिया गया था (धारा 3 के अनुसार केवल उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने इसके तहत जाने की इच्छा व्यक्त की थी। इससे यह मिथक टूट जाता है कि इसने भारतीयों को आपसी आधार पर विभाजित करने की कोशिश की थी।

फिर भी, हिंदुओं, मुसलमानों और विभिन्न अन्य अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानूनों के एक सापेक्ष अध्ययन से पता चलेगा कि इन कानूनों के सरासर मिश्रित गुण, जिस बंद दिमाग वाले उत्साह के साथ उनका पालन करते हैं, वह किसी भी प्रकार की एकरूपता की अनुमति नहीं दे सकता है। दरअसल, हिंदू कानून की विविधता का ही अंतिम लक्ष्य यह है कि एक समान हिंदू कोड की संभावना भी खत्म हो जाती है। अकेले विवाह पर चर्चा करते हुए, विवाह को विभिन्न व्यक्तियों के रीति-रिवाजों और प्रथा के अनुसार संपन्न किया जाना चाहिए जो हिंदू के अर्थ के अंतर्गत आते हैं [9]। उदाहरण के लिए, सप्तपदी प्रकार के विवाह के अनुसार, जो उत्तरी भारत में प्रचलित विवाह का रूप है, विवाह तब पूरा और बाध्यकारी माना जाएगा जब जोड़ा पवित्र अग्नि के चारों ओर सात कदम उठाएगा।

फिर, दक्षिण में सुयमरियाथाई और सेरथिरुत्था प्रकार के विवाह किए जाते हैं। इनके तहत, विवाह वैध है यदि विवाह के पक्ष रिश्तेदारों के सामने घोषणा करते हैं कि वे एक-दूसरे से शादी कर रहे हैं, या यदि वे एक-दूसरे को माला पहनाते हैं, या एक-दूसरे की उंगलियों पर अंगूठी डालते हैं या यदि पति दुल्हन के गले में थाली बांधता है। कानून के तहत वैध विवाह का अभ्यास करने के लिए ये अनुष्ठान अनिवार्य हैं[10]। .इसके अलावा, किसी विवाह को कानून के तहत पर्याप्त/वैध होने के लिए, इसे कम से कम किसी एक पक्ष के मानक रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न किया जाना चाहिए। इस

प्रकार, यदि कोई जैन किसी सिख के रीति-रिवाजों का पालन करते हुए बौद्ध से विवाह करता है, तो विवाह अमान्य है [11]। मुस्लिम कानून में कोई विस्तृत अनुष्ठान या कार्य नहीं हैं, फिर भी सुन्नी और शिया अभ्यास अलग-अलग होते हैं।

परिणामस्वरूप, इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या इन विभिन्न कानूनों को समायोजित करना और एक समान या बुनियादी कोड को परिभाषित करना संभव या व्यावहारिक है जो सभी समुदायों के लिए योग्य हो। भारत में अब तक विशेष विवाहों के संबंध में एक विवेकाधीन सामान्य संहिता है[12]। यह तुलनीय अधिनियमों के साथ पढ़ा जाता है, उदाहरण के लिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, उन व्यक्तियों के लिए विवाह, अलगाव, भरण-पोषण और प्रगति के सभी मामलों के लिए एक सभ्य वैध प्रणाली प्रदान करता है जो धर्म-आधारित कानूनों से बचना चाहते हैं।

वर्तमान स्थिति: सीमित, अप्रवर्तनीय जनादेश

समान नागरिक संहिता और संविधान: तीन मिथकों की कहानी-

सबसे पहले, समान नागरिक संहिता ने स्थापित संवैधानिक नैतिकता के एक अचूक आदेश के रूप में पेश किया है, निदेशक सिद्धांतों में इसकी उपस्थिति इसे वर्णित करने वाले संवैधानिक समझौते का एक निर्विवाद प्रमाण है। [13]

दूसरा, कानूनी घोषणाओं को विकृत करके यह प्रचलित गलत धारणा बना दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक देश के लिए एक कोड के कार्यान्वयन का विश्वसनीय रूप से समर्थन किया है। उचित होना.

तीसरा, एक गलत धारणा को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है कि व्यक्तिगत कानून संविधान के पर्यवेक्षण के अधीन नहीं हैं।

मसौदे के अभाव में, समान नागरिक संहिता का मतलब वही है जो हमें चाहिए - जो कि इस देश की स्पष्ट, असहमति, यहां तक कि झगड़ालू, तनाव और किसी भी अपेक्षा की समग्रता को कम करके आंकना है। स्थापित और कानूनी स्थिति को इन धारणाओं और गलतफहमियों से बचाया जाना चाहिए। यह संविधान के भाग IV के अंतर्गत आता है जिसका शीर्षक राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत है और इसे राष्ट्र पर शासन करते समय याद रखने के लिए राज्य को दी गई सलाह के रूप में समझा जाता है। इन सामान्य हितों की गैर-प्रवर्तनीय प्रकृति के बारे में कभी भी अनिश्चितता का कोई अंश नहीं रहा है। वास्तव में, नीति के निदेशक सिद्धांत की मुख्य मूल व्यवस्था, [14] इनमें से किसी भी मामले को निष्पादन के लिए अदालतों में घसीटे जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों ने यह निश्चित कर दिया है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत , उनकी आकर्षक गुणवत्ता या किसी भी मामले में बोली, संविधान के भाग III में प्रतिष्ठित बुनियादी, लागू करने योग्य और न्यायिक रूप से सुरक्षित व्यक्तिगत और समूह अधिकारों की कीमत पर नहीं मांगी जा सकती है। [15]

अनेक निर्णयों ने केंद्रीय मौलिक अधिकार को राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के साथ उस सीमा तक मिश्रित करने का प्रयास किया, जिस हद तक दोनों के बीच कोई विवाद हो सकता है; अधिकार इन अप्रवर्तनीय अधिदेशों को विश्वसनीय रूप से मात देते हैं।[16] इसका तात्पर्य यह है कि मौलिक अधिकारों को निर्देशक मानकों पर प्रधानता दी गई थी[17]। वास्तव में, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के अंदर भी, सामाजिक कल्याण से संबंधित महत्व और व्यवस्थाओं की एक काल्पनिक श्रृंखला है, मुफ्त विधिक मार्गदर्शन, अनिवार्य निर्देश जो केंद्रीय अधिकारों की पहचान करते हैं और पूरक करते हैं, उन्हें संरक्षित विधि में एक असामान्य स्थान पर सहमति दी गई है।

न्यायिक निर्वचन

न्यायालय इस मामले में कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकती क्योंकि यह नीति का मामला है जिसका फैसला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को करना चाहिये। विधायिका को कानून पारित करने या वीटो करने की शक्ति है। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता के अपील के बारे में पिछले कुछ वर्षों में कुछ छिटपुट टिप्पणियों का उल्लेख किया है; वे संदर्भ के लिए प्रतिबंधित मिसाल कायम नहीं करते हैं। ये टिप्पणियाँ, वैध भाषण में, ओबिटर डिक्टा कहलाती हैं - पारित होने में की गई एक टिप्पणी जिसका विधिक प्रस्थिति के लिए कोई महत्व या प्रोत्साहन नहीं है। कई लोगों का मानना है कि

यह न्यायिक विशेषाधिकार या रणनीति के क्षेत्र में यह चुनने की क्षमता से बाहर है कि कौन सी परंपराएं और प्रथाएं एक समान संहिता में आगे बढ़ेंगी। दरअसल, अदालतों ने एक नियम के रूप में यूसीसी की परेशानी और अव्यवहारिकता पर नियंत्रण पा लिया है और इसके जल्दबाजी में स्वागत के खिलाफ चेतावनी दी है। 2015 के अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर असर डालने से इनकार कर दिया और उस गतिविधि को संसद के दरवाजे पर डाल दिया

हालाँकि, कुछ न्यायाधीश किसी भी मामले में समान नागरिक संहिता को विधिक बहुलवाद के जाल में फंसने के लिए मजबूर करने की संभावना पर विचार कर सकते हैं; वे इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि पर्सनल लॉ के बजाय विधियों को लागू करते समय एकरूपता कोई समाजशास्त्रीय तथ्य नहीं है। हम कानूनों में एकरूपता ला सकते हैं, लेकिन हम प्रतिबद्धताओं और प्रथाओं से एकजुट एक ऐसा आधार कहां खोज पाएंगे जहां राज्य बिना किसी डर या संघर्ष के इन कानूनों को लागू कर सके?

बहुचर्चित शाह बानो मामले [18] में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान होने के कारण सभी पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण की शिक्षा को जोड़ा और प्राधिकरण को विशेष रूप से अपने शाह बानो फैसले के अनुरूप समझा। परिणामस्वरूप, स्थिति यह है कि एक मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत उचित और समझदार भरण-पोषण के लिए योग्य है। जहाँ तक अलगाव के बाद वह अविवाहित है। समान नागरिक संहिता को लेकर विभिन्न घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन उसने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि इस तरह का कानून बनाने के लिए संसद ही उपयुक्त संस्था है। समान संहिता की अपील के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि सभी लोगों के लिए एक ही बार में समान कानून को मंजूरी देना "देश की एकजुटता के लिए प्रतिकूल हो सकता है"। इसके बाद, यह एक कठिन रास्ता है जिस पर सावधानी से चलना चाहिए[19]

धार्मिक अधिकार की भावना

अपने धर्म की प्रत्येक परंपरा और प्रथा के साथ घोषणा करना, भारत के नागरिकों का महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। उपरोक्त सभी संकेतित सांद्रता इन विश्वासों और प्रथाओं का एक "महत्वपूर्ण" हिस्सा हैं। उपरोक्त सभी विषयों के लिए सभी धर्मों में सदियों पुराने रीति-रिवाज़ कम हैं। इन सभी सम्मेलनों की स्थापना महत्वपूर्ण मूल्य के उपायों और विनिमय रीति-रिवाजों के साथ भागीदारी को याद करने पर की गई है। उनमें से एक बड़ा खंड एक-दूसरे के साथ तना बना की तरह बुना हुआ है और पूरे कोड को बिना तैयारी के बदले बिना संशोधित नहीं किया जा सकता है और इस तरह से उस धर्म की सतह को नष्ट कर दिया जा सकता है। यह एक दिलचस्प धर्म बनाने जैसा होगा, जो कुछ भी होगा, जिसकी हमने शुरुआत की थी। इसी तरह, उपरोक्त में से किसी की भी देखरेख/प्रबंधन इन मान्यताओं में स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करेगा और धर्म को मूल रूप से नष्ट कर देगा।

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, **पंथनिरपेक्ष**, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा, उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने के लिए, दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"20

जब संविधान अपने उद्देश्य के रूप में पंथनिरपेक्ष की बात करता है, तो सामाजिक रूप से एक होने की सहमति और प्रतिबद्धता ने संविधान के अनुच्छेद 44 में अपना स्वरूप खोजा। जो भी हो, धार्मिक अवसर, धर्मनिरपेक्षता की मौलिक स्थापना, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 द्वारा सुनिश्चित की गई थी।

अनुच्छेद 25(1) सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं।

(2) इस अनुच्छेद में कुछ भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा-

(ए) किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ा हो सकता है;

(बी) सामाजिक कल्याण और सुधार प्रदान करना या सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खोलना।

स्पष्टीकरण।.- कृपाण धारण करना और धारण करना सिख धर्म के पेशे में शामिल माना जाएगा।

स्पष्टीकरण॥. —खंड (2) के उप-खंड (बी) में, हिंदुओं के संदर्भ को सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, और हिंदू धार्मिक संस्थानों के संदर्भ को तदनुसार माना जाएगा21

सामान्यतः शब्दों में उपबंधित किया गया है। यह सभी लोगों को शांत, अन्तःकरण के लचीलेपन के साथ-साथ धर्म को घोषित करने, विकसित करने और उत्पन्न करने का विशेषाधिकार सुनिश्चित करता है। धर्म क्या है? कोई विश्वास या दृढ़ विश्वास. न्यायालय ने संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई विभिन्न चरणों में धार्मिक स्वतंत्रता का विस्तार किया है और इसे व्यक्ति की भावनाओं और यहां तक कि बाहरी सादे प्रदर्शनों तक बढ़ाया है। धर्म विश्वास का नगण्य विषय है। संविधान ने स्थिर, अन्तःकरण के लचीलेपन को सुनिश्चित करके धार्मिक विश्वास के आंतरिक हिस्सों की गारंटी दी। इसके अलावा, इसकी बाहरी अभिव्यक्ति को अनारक्षित रूप से उचित रूप से सुनिश्चित करने, अभ्यास करने और धर्म को जन्म देने के द्वारा सुरक्षित किया गया था। रामायण या कुरान या बाइबिल या गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ना और प्रस्तुत करना उतना ही धर्म का हिस्सा है जितना कि एक हिंदू द्वारा भगवान को भोजन अर्पित करना या फूलों की वर्षा करना या उसे कपड़े पहनाना और किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में जाना।

विवाह, विरासत, अलगाव, परिवर्तन किसी अन्य दृढ़ विश्वास या विश्वास के समान ही प्रकृति और सार में धार्मिक हैं। अग्नि के सात फेरे लेना या काजी के सामने सहमति देना प्यार की तरह ही आत्मविश्वास और अन्तःकरण का मामला है। जब एक हिंदू कलमा या मुस्लिम का पाठ करके परिवर्तित हो जाता है तो कुछ मंत्रों का पाठ करके स्पष्ट रूप से हिंदू बन जाता है, इसमें दृढ़ विश्वास और शांत आवाज शामिल होती है। एक धर्म के व्यक्तियों द्वारा देखी गई इनमें से कुछ प्रथाएं, सभी दृष्टिकोणों से, अतिशयोक्तिपूर्ण और यहां तक कि दूसरे धर्म के व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली लग सकती हैं। फिर भी, ये विश्वास के विषय हैं। कारण और तर्क की बहुत कम भूमिका होती है। वास्तविक परिश्रम द्वारा अनुमानों और भावनाओं को ठंडा और संयमित किया जाना चाहिए। हालाँकि, वर्तमान समय में कोई राजा राम मोहन राय नहीं हैं जिन्होंने साहसपूर्वक उस माहौल को महसूस किया जो सती उन्मूलन के लिए तैयार था। न ही पंडित जवाहर लाल नेहरू के कद का कोई राजनेता है, जो प्रभावी ढंग से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम के माध्यम से मानक हिंदू विधि को बदल सकते थे। समान संहिता की आकर्षक गुणवत्ता पर शायद ही सवाल उठाया जा सकता है। हालाँकि, यह तभी मूर्त रूप ले सकता है जब सामाजिक माहौल आम जनता के प्रथम वर्ग द्वारा वैध रूप से विकसित किया जाता है, नेताओं के बीच राजनेता जो व्यक्तिगत लाभ बढ़ाने के बजाय आगे बढ़ते हैं और परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए जनता को उत्तेजित करते हैं।

व्यक्तिगत विधि के जबरदस्त भिन्न गुण, साथ ही जिस समर्पण से वे जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की स्थिरता को पूरा करना असाधारण रूप से कठिन बना देता है। जब कोई इस मुद्दे से सरकारी मुद्दों को अलग करने की कोशिश करता है तो अग्रिम मुद्दे सामने आते हैं। किसी भी टिप्पणी, अनुमान या संवाद में निश्चित रूप से कुछ राजनीतिक परिचारक शामिल होते हैं क्योंकि वास्तविक भारतीय राजनीतिक दलों का इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट होता है। एक और मुद्दा यह है कि बहुत से लोग अभी भी यह नहीं समझते हैं कि समान सामान्य कोड का वास्तव में क्या मतलब है। गौरतलब है कि सभी अल्पसंख्यक अभी भी समान नागरिक संहिता के संबंध में गलत व्याख्या के बीच में हैं और इस तरह से इसके संबंध में स्तरीय चर्चा या उनके दृष्टिकोण में उनकी रुचि प्राप्त करना आश्चर्यजनक रूप से कठिन हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि समान नागरिक संहिता के पूर्ण कार्यान्वयन से विभिन्न धर्मों का खोया हुआ सामाजिक चरित्र वापस आ सकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान में एक शब्द बहुत आम और चलन में है और वह है *"समय की मांग"* यह सभी को साथ लेकर चलता है। हम सब नैतिक रूप से बीमार हो गये थे। हममें एक ऐसी प्रवृत्ति विकसित हो गई थी कि हम खुद को सामने रखकर ही किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं। हम हर मुद्दे को खुद ही और कम समय या बिना समय दिए में सुलझाना चाहते हैं। हम उन परिणामों के बारे में जानने की जहमत नहीं उठाते जिनका सामना दूसरों को करना पड़ रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि किसी विधि को अच्छा विधि कहने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि *"इससे सबसे दुखी व्यक्ति का उत्थान होगा या नहीं"*। समान नागरिक संहिता के समर्थकों की वकालत है कि इस विधि से महिलाओं का उत्थान होगा. हमारे पास हिंदू विधि के कुछ उदाहरण हैं, जो संहिताबद्ध हो गए। क्या इससे सचमुच महिलाओं का उत्थान हुआ या उनके विपरीत गया? आँकड़े बताते हैं कि बाद वाला सही है। लेकिन हमें डॉ.बी.आर.अम्बेडकर की चेतावनी नहीं भूलनी चाहिए.,

"कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं, तो वह बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे हैं, तो वह अच्छा साबित होगा।"

हालाँकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान के लिए कहा था, लेकिन यह हर कानून पर खरा उतरता है और पर्सनल लॉ भी इसका अपवाद नहीं है। हमें ज्ञान प्रदान करने और समुदायों के भीतर एक ज्ञान का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे स्वयं समान नागरिक संहिता के लिए आगे बढ़ें और एक कानून बनाएं, एक अच्छा विधि, चाहे विधि अच्छा हो या बुरा। यदि आम जनता इसे नहीं समझती है तो विधि का जबरदस्ती कार्यान्वयन अंततः विफल हो जाएगा। बदले में, यह विधि की अवहेलना का एक बड़ा विस्फोट देगा और इससे अधिक कुछ नहीं।

यदि हम बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाते हैं तो पुरुष बहुविवाह करते रहेंगे। आप ऐसे रिश्तों में महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे? जब हम लैंगिक न्याय के दृष्टिकोण से इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं तो यह मुख्य मुद्दा है। कई बार महिलाओं को पहली शादी के बारे में पता होता है तो कई बार पुरुष जानबूझकर जानकारी छिपा लेते हैं। उनके पर्सनल लॉ के अनुसार मुसलमानों को बहुविवाह की अनुमति है, प्रत्येक विवाहित महिला को समान दर्जा प्राप्त है और उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो पुरुष इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, महिलाओं का यौन शोषण कर सकते हैं और फिर उन्हें कानून का उल्लंघन करने के लिए बिना किसी आर्थिक परिणाम के छोड़ सकते हैं, केवल यह कहकर कि महिला उनकी दूसरी पत्नी है और उनकी पहली शादी कायम है। इसके कारण घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में "विवाह जैसा रिश्ता" शब्द गढ़कर ऐसे रिश्ते में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया।

इस देश में पहले ज़मीन तैयार करनी चाहिए, फिर यदि बीज बोया जाए तो पौधा उत्तम निकलेगा और यदि बीज की प्रकृति के विरुद्ध कार्य किया जाए तो वह अंततः नष्ट हो जाएगा। हमें किसी को वैसा सोचने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जैसा दूसरे सोच रहे हैं। हमें लोगों को इन अवधारणाओं को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए और यह केवल ज्ञान प्रदान करके ही किया जा सकता है, न कि विधि या बहुमत के अत्याचार से। एक ओर हमें सहिष्णुता बढ़ानी चाहिए और दूसरी ओर हमें समान नागरिक संहिता की अवधारणा को दूसरों को समझाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए और इसके विपरीत यदि हम असहिष्णु हो जाते हैं तो कानून का लक्ष्य और उद्देश्य गायब हो जाएगा और एक बार जब कोई असहिष्णुता का रवैया अपना लेता है, तो यह नहीं पता होता है कि यह उसे कहां ले जाएगा। किसी ने कहा है कि असहिष्णुता बुद्धि के लिए हिंसा है और घृणा हृदय के लिए हिंसा है। असहिष्णुता और बुद्धि दो विपरीत ध्रुव हैं और जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें लोगों को अपने व्यवसाय को स्वयं समझने और निपटाने देना चाहिए, भले ही यह मानक नैतिकता के थोड़ा विपरीत हो क्योंकि गलती करने की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता का मूल है जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहा था:

"जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है"

सुझाव

सबसे पहले, एकल और समान कानून के तहत विविध व्यक्तिगत कानूनों को लाने के बजाय व्यक्तिगत कानूनों में सुधार लाकर समान नागरिक संहिता के बारे में अवधारणा का पुनर्गठन करना बहुत महत्वपूर्ण है।

दूसरे, व्यक्तिगत कानूनों के बीच टकराव को दूर करने के संबंध में नए कानून बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

तीसरा, किसी भी पर्सनल लॉ के मूल्यों के संबंध में स्पष्ट समझ होनी चाहिए और उसकी अधिकतम भावना का सम्मान किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ सूची: -

[1] स्वामी विवेकानन्द, शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद को सम्बोधित करते हुए (11-17 सितम्बर)

[2] रिचर्ड श्वेडर, एंगेजिंग कल्चरल डिफरेंसेज: द मल्टीकल्चरल चैलेंज इन लिबरल डेमोक्रेसी (रसेल सेज फाउंडेशन)

[3] जॉर्ज ब्यूहलर, द लॉज़ ऑफ़ मनु 830 (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 25वां खंड, 2005)

[4] वर्नर मेन्स्की, हिंदू लॉ: बियॉन्ड ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी 126 (दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड यू.पी., 2003)

[5] टिमोथी लुबिन और अन्य, हिंदू धर्म और कानून: एक परिचय अध्याय 1 (लुबिन और डेविस, 2010)

[6] तदैव

[7] कुणाल पार्कर, रिलिजन एंड पर्सनल लॉ इन सेक्युलर इंडिया: ए कॉल टू जजमेंट 184-199 (जेराल्ड जेम्स लार्सन, 2001)

[8] चंद्र मल्लमपल्ली, औपनिवेशिक दक्षिण भारत में ईसाई और सार्वजनिक जीवन: 1863-1937 59-64 (रूटलेज, 2004)

[9] हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

[10] तदैव

[11] शकुंतला बनाम नीलकंठ और अन्य, (1973) एमएच। एल जे 310.

[12] विशेष विवाह अधिनियम, 1954

[13] अनुच्छेद 44, भारत का संविधान, 1949

[14] अनुच्छेद 37, भारत का संविधान, 1949

[15] पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2004 8 एससीसी 139

[16] मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरैराजन, एआईआर 1951 एससी 226

[17] सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 845 (1965) एससीआर (1) 933.

[18] मो. अहमद खान बनाम शाह बानो, एआईआर 1985 एससी 945

[19] पन्नालाल बंसीलाल पाटिल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1996) 2 एससीसी 498

[20] प्रस्तावना , भारत का संविधान, 1950

[21] अनुच्छेद 25, भारत का संविधान, 1950